भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

18.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3830 का उत्तर

अगले दशक में नई पटरियां

3830. श्री राहुल कस्वां:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अगले दशक में 50,000 किलोमीटर नई पटरियां बिछाने के लिए 7 ट्रिलियन रुपये के निवेश के सफल कार्यान्वयन हेतु कोई विस्तृत कार्य योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस महत्वाकांक्षी परियोजना, विशेषकर राजस्थान के लिए निर्धारित की गई विशिष्ट लक्ष्य और समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या सरकार की उस क्षेत्र में बेहतर रेल संपर्क की मांग को देखते हुए वंदे भारत सेवाओं को चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तक विस्तारित करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो इस विस्तार का आकलन करने और इसे कार्यान्वित करने के लिए की जा रही कार्रवाइयों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृत/निष्पादित क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है, न कि राज्य-वार/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाएं

लाभप्रदता, यातायात अनुमान, अंतिम छोर तक पहुंच, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्ग, भीड़भाड़/संतृप्त लाइनों के विस्तार, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकता, सामाजिक-आर्थिक महत्वों आदि के आधार पर स्वीकृत की जाती है, जो चल रही परियोजनाओं के थ्रोफॉरवर्ड और धन की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

यात्रियों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही और संभार तंत्र दक्षता बढ़ाने के लिए, वर्तमान में, प्रधान मंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत औद्योगिक समूहों, कृषि क्षेत्रों, बंदरगाहों, खदानों, बिजली संयंत्रों, दूर-दराज के क्षेत्रों, पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों आदि से जोड़ने के लिए लगभग 49,520 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले 624 अदद सर्वेक्षणों (नई लाइनें, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण) को मंजूरी दी गई है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में, कुल 44,488 किलोमीटर लंबाई की लगभग 7.44 लाख करोड़ रुपये लागत वाली 488 रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं (187 नई लाइन, 40 आमान परिवर्तन और 261 दोहरीकरण), योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं, जिनमें से 12,045 किलोमीटर को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक लगभग 2.92 लाख करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। कार्य का सार निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की सं.	नई लाइन/आमान परिवर्तन/दोहरीकरण की कुल लंबाई (कि.मी.)	मार्च, 2024 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी.)	मार्च 2024 तक किया गया कुल व्यय (करोड़ रू. में)
नई लाइन	187	20199	2855	160022
आमान परिवर्तन	40	4719	2972	18706
दोहरीकरण/ मल्टीट्रैकिंग	261	19570	6218	113742
कुल	488	44,488	12,045	2,92,470

लागत, व्यय और परिव्यय सहित सभी रेल परियोजनाओं का रेल-वार/वर्ष-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया है।

भारतीय रेल में नई पटरियों को कमीशन/बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथों की औसत कमीशनिंग
2009-14	7,599 कि.मी.	4.2 किमी. प्रति दिन
2014-24	31,180 कि.मी.	8.54 कि.मी. प्रति दिन (2 गुना से अधिक)

राजस्थान राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं।

लागत, व्यय और परिव्यय सहित रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार विवरण भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध करा दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2021-2022, वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, 15150 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 1262 किलोमीटर लंबाई की कुल 19 परियोजनाएं (नई लाइन, दोहरीकरण और आमान परिवर्तन) स्वीकृत की गई हैं, जो पूर्णतः/अंशतः राजस्थान राज्य में आती हैं।

01.04.2024 तक, राजस्थान राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 51,814 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 4,191 किलोमीटर लंबाई की 32 रेल परियोजनाएं (15 नई लाइनें, 5 आमान परिवर्तन और 12 दोहरीकरण), निष्पादन और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 1,183 किलोमीटर कुल लंबाई की रेल लाइन कमीशन की गई है और मार्च, 2024 तक 14,786 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। कार्य की स्थिति निम्नानुसार है:-

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की सं.	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रू.में)
नई लाइन	15	1230	134	3593
आमान परिवर्तन	5	1252	759	5398
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	12	1709	290	5794
कुल	32	4191	1183	14786

इन परियोजनाओं में चूरू-रतनगढ़ दोहरीकरण (42.81 किमी) और चूरू-सादुलपुर दोहरीकरण (57.82 किमी) शामिल हैं, जो पूर्णतः/अंशत: रूप से चूरू में पड़ती है।

राजस्थान में पूरी तरह से/आंशिक रूप से आने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आवंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	682 करोड़ रु. प्रतिवर्ष
2014-24	9,959 करोड़ रु. (14 गुना से अधिक)

वर्ष 2009-14 और 2014-24 के दौरान राजस्थान राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाले नये रेलपथ को कमीशन किए जाने/बिछाने का विवरण निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथों की औसत कमिशनिंग
2009-14	798 कि.मी.	159.6 कि.मी./वर्ष
2014-24	3,742 कि.मी.	374.2 कि.मी./वर्ष (2 गुना से अधिक)

किसी भी रेल परियोजना का पूरा होना, राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, लागत हिस्सेदारी परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत हिस्सेदारी जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, अतिलंघनकारी जनोपयोगिताओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरी, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण विशेष परियोजना स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों (i) गति शक्ति इकाइयों की स्थापना, (ii) परियोजनाओं को प्राथमिकता देना, (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए निधि के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि, (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन, (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी, और (vi) भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव मंजूरी में तेजी लाने तथा परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप 2014 से कमीशनिंग की दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

वर्तमान में, चूरू को 46 मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों द्वारा सेवित किया जा रहा है, जिनमें 02 दुरंतो एक्सप्रेस सेवाएं और 14 यात्री रेलगाड़ी सेवाएं शामिल हैं, जो चूरू को मुंबई, कोयम्बटूर, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, जम्मू तवी, साईं नगर शिरडी, रामेश्वरम, इंदौर, जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा आदि जैसे गंतव्यों से जोड़ती हैं।

इसके अलावा, यात्रियों की अतिरिक्त ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, चूरू स्टेशन पर 06 स्पेशल रेलगाड़ियाँ भी चलाई जा रही हैं। इसके अलावा, भारतीय रेल पर परिचालनिक

व्यवहार्यता, यातायात औचित्य, संसाधनों की उपलब्धता आदि के अध्यधीन, वंदे भारत सहित रेलगाड़ी सेवाओं का विस्तार करना सतत् प्रक्रिया है।

*****